



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2008/श्रावण 9, 1930

No. 268]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2008/SRAVANA 9, 1930

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2008

सं. जेड-11025/229/2006-उत्प्रवास.—भारत सरकार, प्रवासी रोजगार के संवर्धन, प्रवासी भारतीय कामगारों के बेहतर संरक्षण और कल्याण के लिए तथा उभरते प्रवासी रोजगार अवसरों का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक समझती है कि एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की जाए। एक स्वतंत्र निकाय की तत्काल आवश्यकता है। जो एक नीतिगत 'चिन्तन सागर' के रूप में कार्य कर सके और यथाशीघ्र आधार पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार में होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके।

2. इसलिए, भारत सरकार ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी सोसायटी के रूप में एक प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद् की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

3. प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद् में निकाय के दो स्तर होंगे जिनमें एक शासी निकाय और दूसरा एक कार्यकारी निदेशालय। शासी निकाय की संरचना निम्नलिखित अनुसार होगी :

- (I) सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय —अध्यक्ष
- (II) निम्नलिखित परिषद् के अन्य सदस्य होंगे :
 - i. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, अथवा उनके प्रतिनिधि
 - ii. सचिव, विदेश मंत्रालय, अथवा उनके प्रतिनिधि
 - iii. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अथवा उनके प्रतिनिधि
 - iv. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अथवा उनके प्रतिनिधि
 - v. सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय अथवा उनके प्रतिनिधि

vi. उत्प्रवासी भेजने वाले प्रमुख राज्यों में से प्रत्येक दो वर्ष में बारी-बारी से राज्य सरकारों के तीन सचिव।

vii. प्रत्येक दो वर्ष की अवधि के लिए सरकार द्वारा नामित चार विशेषज्ञ।

viii. परिषद् का कार्यकारी निदेशक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

4. कार्यकारी निदेशक, जोकि परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, कार्यकारी निदेशालय का नेतृत्व करेगा। शासी निकाय परिषद् के विनियमों के अनुसार, कार्यकारी निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता के लिए आवश्यक सचिवालयीय और व्यावसायिक स्टाफ की नियुक्ति करेगा।

5. शासी निकाय परिषद् के उद्देश्यों के अनुरूप इसके कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए व्यापक नीति संरचना तैयार करेगा। कार्यकारी निदेशालय नीतियां तैयार करेगा और शासी निकाय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों/परियोजनाओं को कार्यान्वित करेगा।

6. परिषद् मौटे तौर पर निम्नलिखित कार्य करेगी :

- i. विदेशों में देश/क्षेत्र परक उभरते रोजगार अवसरों के बारे में डाटा आधार तैयार करना और उसे बनाये रखना।
- ii. विदेशी श्रम बाजार में श्रम आपूर्ति फासलों का पता लगाना और इन फासलों को पाटने के लिए भारतीय श्रमिकों द्वारा अपेक्षित कौशल मानकों का पता लगाना।
- iii. व्यावसायिक निकायों और निजी क्षेत्र से परामर्श करके कौशल विकास और कौशल उन्नतीकरण के लिए कार्यक्रम शुरू करना और विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ाना।

- iv. विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए विदेश जाने से पूर्व के कार्यक्रम शुरू करना ।
- v. राज्य मानव शक्ति विकास निगमों, परियोजन मानव शक्ति सप्लायर्स और विदेशी नियोक्ताओं सहित अन्य रोजगार संवर्धन एजेंसियों के साथ समन्वय करना ।
- vi. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम बाजार के रूखों और विशेषताओं, भारत और विदेशों में उत्प्रवासी भारतीय श्रमिकों के सम्मुख आ रही समस्याओं का अध्ययन, निगरानी और विश्लेषण आरम्भ करना और उनमें सहायता करना, श्रमिक भेजने वाले अन्य देशों की सर्वोत्तम प्रणालियों और की जाने वाली पहल/नीतियों को अपनाना ।
- vii. प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए आवश्यकता आधारित कल्याण सहायता प्रदान करना जिनमें इस उद्देश्य के लिए एक कल्याण कोष के संस्थागत प्रबंध करना शामिल है ।

7. परिषद् के खर्च को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के बजट में से अनुदान प्रदान करके पूरा किया जाएगा ।

8. प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद् सरकार से दूर रहकर कार्य करेगी और ठोस सार्वजनिक-निजी साझेदारियां बनाने, दावाधारकों में क्षमता सृजन करने में सक्रिय रूप से भाग लेने और प्रवासी रोजगार अवसरों से मध्यावधि और दीर्घावधि लाभ प्राप्त करने के लिए भारतीय कामगारों के लिए बेहतर बाजार तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण नीतियां कार्यान्वित करने में उसे अपेक्षित स्वायत्तता और लोचशीलता होगी ।

9. प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद् इस संकल्प के जारी होने की तारीख से गठित की जाएगी ।

जी. गुरुचरण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS RESOLUTION

New Delhi, the 31st July, 2008

No. Z-11025/229/2006-Emig.—The Government of India considers it necessary to establish an institutional mechanism for the promotion of overseas employment, better protection and welfare of overseas Indian workers and for the study of emerging overseas employment opportunities. There is an urgent need for an independent body that can function as a strategic 'Think Tank' and can respond to the changes in the international labour market on a real time basis.

2. The Government of India has, therefore, decided to establish a 'Council for Promotion of Overseas Employment' (CPOE) as a Not-For-Profit Society registered under Registration of Societies Act, 1860.

3. The Council for Promotion of Overseas Employment will be a two-tier body comprising a Governing Body and an Executive Directorate. The constitution of the Governing body will be as follows :—

(I) Secretary, Ministry of Overseas Indian Affairs — Chairman

(II) The following shall be the other members of the Council :

- i. Secretary, Department of Economic Affairs or his representative
- ii. Secretary, Ministry of External Affairs or his representative
- iii. Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises or his representative
- iv. Secretary, Ministry of Labour and Employment or his representative
- v. Secretary, Ministry of Overseas Indian Affairs or his representative
- vi. Three Secretaries of the State Governments by rotation every two years from amongst the major emigrant sending States
- vii. Four experts to be nominated by the Government for a term of every two years
- viii. The Executive Director of the Council will function as Member Secretary.

4. The Executive Director, who will be the Chief Executive Officer of the Council, will head the Executive Directorate. The Governing Body will appoint, as per the regulations of the Council, necessary secretarial and professional staff to assist the Executive Director/Chief Executive Officer.

5. The Governing Body will provide the broad policy framework for the programmes and activities of the Council in consonance with its objectives. The Executive Directorate will evolve strategies and implement the programmes/projects for achieving the goals set by the Governing Body.

6. The Council will perform the following broad functions :

- i. Build and maintain a database on emerging country/sector specific employment opportunities abroad.
- ii. Identify labour supply gaps in overseas labour markets and the skill sets required by Indian workers to fill those gaps.
- iii. Initiate programs for skill development and skill upgradation in consultation with professional bodies and the private sector and promote employment opportunities abroad.
- iv. Initiate pre-departure orientation programs for various categories of workers.
- v. Coordinate with other employment promotion agencies, including the state manpower development corporations, project manpower suppliers and foreign employers.

- vi. Initiate and support the study, monitoring and analysis of the trends and dynamics of international labour market, problems faced by the emigrant Indian workers in India and abroad, benchmark the best practices of other labour sending countries and recommend policy initiatives/strategies.
 - vii. Administer need based welfare support for overseas Indian workers including through institutional arrangements of a welfare fund for the purpose.
7. The expenditure of the Council will be met by providing grants from the budget of the Ministry of Overseas Indian Affairs.

8. The Council for Promotion of Overseas Employment will work at 'arms-length' from government and will have the required autonomy and flexibility to build strong public-private partnerships, engage proactively in capacity building across stake-holders and implement well calibrated strategies for better market access for Indian workers to benefit from overseas employment opportunities in the medium to long-term.

9. The Council for Promotion of Overseas Employment shall be constituted with effect from the date of notification of this resolution.

G. GURUCHARAN, Jt. Secy.